



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58484

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7873 वर्ष 2026

नज़ीम उर्फ नगीम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: ए.जेड. खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक, नज़ीम उर्फ नागीम की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद अपराध संख्या- 543/2025, धारा 109(1), 352 और 3(5) के तहत, मंडी पुलिस स्टेशन, जिला सहारनपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदक नज़ीम उर्फ नागीम और सह-आरोपियों ने नवाब को धारदार हथियार से चोट पहुंचाई है।

5. आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एफआईआर में आवेदक को घायल को चोट पहुंचाने का सामान्य और सामान्य आरोप दिया गया है और घटना रात में घटी बताई गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता श्रीमती फरहाना, जो घायल नवाब की पत्नी बताई जाती हैं, के बयान में भी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में आरोपी-आवेदक की स्पष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि घायल नवाब के बयान में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के संबंध में सह-आरोपी जावेद को विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका सौंपी गई है। वह यह भी तर्क देता है कि चिकित्सा रिपोर्ट में छह चोटें दर्शाई गई हैं, जिनमें से दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं चोटें चीरे के घाव हैं। ये चोटें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर बताई गई हैं, लेकिन ये चोटें आरोपी-आवेदक द्वारा नहीं पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका हलफनामे के अनुच्छेद 21 में विधिवत वर्णन किया गया है। आवेदक 18.12.2025 से जेल में बंद है। इसके अलावा, माननीय एजीए के अनुसार, इस मामले में 17.01.2026 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। निवेदन यह है कि मुकदमे की सुनवाई में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि विचारपूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

7. यह देखते हुए कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक नज़ीम उर्फ नागीम का नाम एफआईआर में सह-आरोपी जावेद के साथ दर्ज है, लेकिन आरोपी-आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है, न तो एफआईआर में और न ही घायल व्यक्ति के बयान में, और न ही शिकायतकर्ता श्रीमती फरहाना के बयान में, धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के लिए। सह-आरोपी जावेद, अभियुक्त-आवेदक नज़ीम उर्फ नागीम का सगा भाई बताया जाता है। घायल नवाब ने सह-आरोपी जावेद की भूमिका और संलिप्तता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने चाकू की मदद से घाव किए थे, और अभियुक्त-आवेदक नज़ीम उर्फ नागीम की भूमिका और संलिप्तता केवल उकसाने की बताई गई है। यह स्वीकार किया जाता है कि घाव के निशान/चिकित्सा साक्ष्य घायल नवाब के बयान से मेल खाते हैं, लेकिन उक्त चोटें सह-आरोपी जावेद द्वारा पहुंचाई गई बताई जाती हैं, जो आरोपी आवेदक का सगा भाई है। विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में 17.01.2026 को पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। आरोपी-आवेदक 18.12.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे के निष्कर्ष को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यापक अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अनुच्छेद संख्या 53, 2024 (एससी) मुकदमा 677, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए। (2022) 10 एससीसी 51** और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके और **दो भारी जमानतों** को समान राशि में न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले किया जाएगा।

20 मार्च, 2026

के.एन

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”